International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
Vol. 4, Issue 2, February 2017 Impact Factor- 5.414
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
© Associated Asia Research Foundation (AARF) Publication
Website: www.aarf.asia Email : editoraarf@gmail.com

कोयला क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की स्थिती का अध्ययन

पो. एल. नागपुरे
सहयोगी प्राध्यापक
एम. बी. पटेल महाविद्यालय
देवरी, जि. गोंदिया (महाराष्ट्र)

सारांश

कोयला उत्पादन का इतिहास भारत में लगभग 225 वर्ष पुराना है। भारत में कोयला उद्योग विकास की एक ऐसी संघर्ष मई यात्रा है, जो विभिन्न उतार चढाव के बाद उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर रही है। कोयला क्षेत्र दिन दुनि प्रगति पर होने के बावजुद कोयला श्रमिकों की प्रगती उस हिसाब से नही हुयी है। प्रस्तुत लेख मे. कोयला क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की स्थिती का अभ्यास किया गया है।

मुख्य शब्द : कोयला, श्रमिक, प्रणाली

प्रस्तावना

विभिन्न सम्भावनाओं एवं कल्पनाओं के बीच एक और अनउत्तरित प्रश्न भी ''यक्ष प्रश्न'' की भांति हमेशा सामने रहता था कि ब्लास्टिंग की भयानक आवाजों, आये दिन खदानों में होने वाली हृदय विदारक घटनाओं जिनमें न जाने कितने ही व्यक्ति घायल होते हैं अथवा अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इसके बावजूद खदानों में ऐसी कौनसी बात है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक ओर तो श्रमिकों की हडतालों के समाचार आम रहते हैं, वहीं दूसरी ओर वे हडताली श्रमिक भी इन खदानों के प्रति इतना लगाव और उत्सर्ग की भावना क्यों रखते हैं? यह भी कम आश्चर्य की बात नही है, कि जन सामान्य की अभिरूचि दिनो दिन इन कोयला खदानों और वहॉ के कर्मचारियों के प्रति अधिक क्यों होती जा रही है। इन्ही सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के प्रयास में मेरे पास जमुना–कोतमा क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक एंव सामाजिक स्थितियों का एक अस्पष्ट सा चित्र बनता चला गया।

कोयले का महत्व :

घरेलू ईंधन से औद्योगिक विकास की आधार शिला तक की यात्रा में ''कोयला'' ने सदैव अपना महत्व प्रतिपादित किया है। कोयले के अभाव में किसी राष्ट्र की औद्योगिक एंव आर्थिक प्रगति की कल्पना असम्भव सी प्रतीत होती है, एंव मानव जीवन के प्रत्येक पहलू में कोयले का महत्व है ही। प्रमुख वाणिज्यिक उर्जा श्रोत के रूप में भी कोयला सर्व मान्य है। भारत में उर्जा विकल्पों की सघन खोज के उद्देश्य से सत्तर के दशक में सुविख्यात अर्थशास्त्री प्रो. सुशानराय चौधरी के अध्यक्षता में ईंधन नीति समिति गठित की गई थी। इस समिति द्वारा भी कोयला को देश के प्रमुख वाणिज्यिक उर्जा श्रोत के रूप में स्वीकृत किया गया था। यही कारण है कि कोयले को काला हीरा के नाम स भी सम्बोधित किया जाता है।

विद्युत शक्ति विकास की प्रथम आवश्यक्ता है। इस शक्ति के बिना बडे कल कारखानों एंव परिवहन सुविधाओं दोनों का चलते रह सकना सम्भव नहीं है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 66 प्रतिशत एंव सम्पूर्ण विश्व में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत ताप विद्युत संयत्रों पर निर्भर है। इन ताप विद्युत संयत्रों में विद्युत उत्पादन हेतु ईंधन के रूप में कोयला ही प्रस्तुत किया जाता है।

विकास की दूसरी प्रमुख आवश्यक्ता लोहा, इस्पात एंव सीमेण्ट है। खनिज से लोहे के निष्कर्षण एंव लोहा से इस्पात बनाने की प्रक्रिया में कोयले के तीनों रूप हार्डकोल, कोकिंग कोल एंव कोक की आवश्यता होती है। लोहे के धातु कर्म में कोकिंग कोल के प्रयोग से विगलित धातुमल की श्यानता भी बढती है। फलतः धातु को अधिक शुध्द रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार सीमेण्ट निमाण प्रक्रिया में प्रयुक्त ल्किन (भट्ठी) को चलाने हेतु भी ईंधन के रूप मे कोयले का ही प्रयोग किया जाता है।

भारत के कुल विदेशी व्यापार का एक बहुत बडा प्रतिशत धातु के बर्तन एंव मूर्तियों के निर्यात पर निर्भर करता है। इस हेतु धातु निष्कर्षण एंव धातु कर्म उद्योगों में भी कोयले का विशेष महत्व है।

विश्व में खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उर्वरक की आवश्यक्ता से इंकार करना सम्भव नहीं है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जो उर्वरक एक प्रमुख आवश्यक्ता है। वही उर्वरक उद्योग में भारी मात्रा में कोयले का उपयोग होने के कारण इस क्षेत्र में कोयले का महत्व असंदिग्ध है।

भारत में कोयला उद्योगः

किसी भी देश का विकास उस देश की कुल उत्पादन क्षमता पर और उत्पादन क्षमता प्रायः उपलब्ध प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करती है। राष्ट्र के अविकसित या अल्पविकसित रह जाने का मूलकारण प्रायः यह होता है, कि प्राकृतिक संसाधन या तो अप्रयुक्त या अल्प प्रयुक्त या दुश प्रयुक्त रहते हैं। ध्यान देने योग्य है कि प्राकृतिक साधनों का पूर्ण रुपेण एवं विधिवत सुरक्षित दोहन ही आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की आधार शिला है।

औद्योगिक विकास का अर्थ उद्योग का नियमित एवं क्रमिक विकास है। जिसमें उद्योगों में धीरे धीरे नवीनता एवं आधुनिकता का समावेश होता है। उत्पादन एवं सेवाओं के प्रति उदासीनता, अनुसंधान की कमी एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव में औद्योगिक विकास की कल्पना करना निरर्थक मानसिक श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। अपवाद रुप में एक तथ्य यह भी है कि प्राकृतिक साधनों के अभाव में भी औद्योगिक एवं आर्थिक विकास सम्भव है। जापान इसका ज्वलन्त उदाहरण है। जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद जागरुकता और अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति के माध्यम से तकनीकी ज्ञान को विकसित करके सर्वाधिक आधिक्य वाला दे"ा बनने का गौरव प्राप्त किया है।

भारत में कोयला उद्योग विकास की एक ऐसी संघर्षमय यात्रा है जो विभिन्न उतार चढाव के साथ उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर रही है।

भारत में निजी कोयला उद्योग का सूत्रपात 1815 में श्री विलियम जोन्स के हाथों हुआ श्री जोन्स को भारत के आधुनिक कोयला खनन का सूत्रपात करने का श्रेय प्राप्त है। श्री जोन्स द्वारा रानीगंज क्षेत्र में कोयला खनन प्रारम्भ किये जाने के पश्चात देश के विभिन्न कोयला क्षेत्रों की खोज और कोयला उद्योगों की स्थापना हुई।

कोयले का मूल्य एवं विपणन व्यवस्था :

राष्ट्रीयकरण के पूर्व भारत में निजी क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा कोयला उत्खनन की लागत पर वि"ोष नियंत्रण लगाये जाते रहे, फलतः श्रम शक्ति का दोहन एवं शोषण बढता ही जा रहा था। परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र की यह बुराई एवं कमजोरी है, कि कोयला की उत्पादन लागत पर नियंत्रण एवं कोयला क्षय की रोकथाम में यहाँ के सक्षम अधिकारियों द्वारा उदासीनता बरती जाती है। फलस्वरूप उत्पादन लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसी स्थिती में अंतिम परिणाम यह होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की लाभकारिता प्रायः समाप्त होने लग जाती है। आज के परिवे"ा में कोयला उद्योग की यही द"ाा हो गई है। यदि इस दि"ाा पर गंभीरता से विचार कर सुधार न किया गया तो कोल इण्डिया लिमिटेड

निकट भविष्य में ही टूटती–बिखरती दिखाई पडेगी। शासन इसमें सुधार करने की अपेक्षा एकाधिकारी मूल्य निर्धारण कर लाभ अर्जित करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि राष्ट्रीयकरण के पूर्व कोयले के मूल्य में और आज के कोयले के मूल्य में गुणात्मक वृध्दि दिखाई पडती है। जो राष्ट्र के लिए कदाचित हितकारक नहीं है।

कोयले की विपणन व्यवस्था :

कोयले की मांग पूरे दे"ा में बढ़ती जा रही है। कोयले की विक्री एवं मांग की पूर्ति करने का कार्य कोयला क्षेत्र के मार्केटिंग आफीसर एवं मार्केटिंग विभाग द्वारा किया जाता है। चूंकि कोयला उदयोग राष्ट्रीय कृत उद्योग है, और निजी कम्पनियाँ कोयला उद्योग का कार्य नही कर सकती, इस लिए कोल इण्डिया का उत्तर दाइत्व और अधिक हो जाता है कि पूरे दे"ा में हो रही कोयले की मांग को देखते हुए तदनुसार उत्पादन में वृद्धि करें और मांग एवं पूर्ति का सन्तुलन बनाये रखें।

श्रम कल्याण कार्य :

जमुना – कोतमा क्षेत्र कोयला उद्योग का क्षेत्र है। कोयला उद्योग में तीन शिफ्टमें उत्पादन कार्य होता है। इस उद्योग के अधिकांश श्रमिकों को शिफ्ट ड्यूटी करनी पड़ती है। प्रथम शिफ्ट प्रातः सात बजे से दोपहर तीन बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर तीन बजे से रात्रि ग्यारह बजे तक तथा तीसरी शिफ्ट रात्रि ग्यारह बजे से प्रातः सात बजे तक एवं प्रत्येक कर्मचारी की एक सप्ताह क अन्तर में शिफ्ट बदल जाती है। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी को कभी प्रथम, कभी द्वितीय और कमी तृतीय शिफ्ट में ड्यूटी करनी पडती है। इसके अतिरिक्त भूमिगत खान में कार्यरत श्रमिक को आठ घण्टे अपना कार्य खदान के अन्दर रह कर तथा खुली खदान में जमीन की सतह से लगभग 50 मीटर नीचे उत्पादन कार्य स्थल पर रह कर कार्य करना पडता है। इस प्रकार कोयला उद्योग के कर्मचारियों का कार्य बहुत कठिन तथा परिश्रम का कार्य है।

सामाजिक सुरक्षा से आशय :

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज मे ही पैदा होता है, समाज में ही पलता है। सामाजिक प्राणो होने के नाते उसका सीधा सम्बन्ध समाज से रहता है। समाज में अपने आप को सामाजिक व्यक्ति के रूप मे स्थापित करने के लिए, उसे सामाजिक प्रतिस्पर्धा में जीवन जीना पड़ता है, और भारतीय परम्परा के अनुसार एक व्यक्ति परिवार में कमाता है, और पूरा परिवार पलता है। किन्तु उस कमाने वाले व्यक्ति के साथ कोई आकस्मिक घटना घटे या वह व्यक्ति किसी दुर्घटना का सिकार हो जाये या फिर

उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाय तो ऐसी स्थिति में पूरे परिवार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खडी हो जाती है, कि अब परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। समाज में वह परिवार कैसे सुरक्षित रहे। इन सभी स्थितियों और प्रश्नों पर विचार करने के बाद, कोयला उद्योग ने अपने कर्मचारियों और कर्मचारियों के परिवारजनों की समाज में किसी भी परिस्थिति में सम्मान जनक स्थिति बनाये रखने के उद्देश्य से अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का बल प्रदान कर रखा है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा से आशय उस सुरक्षा से है, जिसकी मनुष्य को समाज में खडे रहने के लिये उसके असहाय हो जानेवाले दिनों में आवश्यकता होती है या उसके न रह जाने पर उसके परिवार जनों को आवश्यकता होती है उसे सामाजिक सुरक्षा कहते हैं।

निष्कर्ष

क्षेत्र में पिछडेपन के कारण लोगों की आवष्यक्तायें बहुत सीमित थीं, जिसके कारण यहाँ के लोगों का ध्यान रोजगार या किसी उद्यम की ओर नहीं जाता था और पर्याप्त मानव शक्ति होने के बाद भी इसका उपयोग नहीं हो पाता था। जैसे –जैसे सामाजिक उत्थान हुआ, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, वैसे–वैसे अधिक आय की आवष्यकता होने लगी और व्यर्थ में जा रही मानव शक्ति का उपयोग होने लगा, जो देश हित के लिए अति आवष्यक है। कोयला उद्योग का इतिहास साक्षी है – अनेकों उतार चढाव और श्रमिकों की कुर्बानियों से भारत का कोयला उद्योग आज उच्चतम स्थिती तक पहुंचा है। किन्तु आज के परिवेष में कोयला उद्योग का भविष्य खतरे में दिखाई पड़ता है। कोयला क्षेत्र में श्रमिकों को नियमानुसार वेतन भुगतान बोनस भुगतान तथा प्राफिट शेयरिंग बोनस का भुगतान समयानुसार किया जाता है। किन्तु अन्य सुविधा एल.टी.सी. भुगतान, घुंट्टी की स्वीकृति तथा क्षतिपूर्ति भुगतान आदि में कामगारों को काफी परेशानी उठानी पडती है, यह सुविधा समय से उपलब्ध नहीं हो पाती है। जिसके कारण श्रमिकों में असन्तोष बढता है। कोयला खदान क्षेत्र में श्रमिकों का जीवन स्तर सामान्य है, तथा षिक्षा के प्रति अच्छा जागरूकता नही है। श्रमिकों को षिक्षा के बारे में जाणकारी दे कर उनको अथा उनके बच्चो को शिक्षा के अवसर प्रदान किये जाये।

संदर्भ

- खान व्यवसायिक प्रशिक्षण विनियम 1966 (श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय)Amended up to date 2004
- कोल माइन्स रेग्यूलेशन 1957
- Modern Coal mining Technology [Dr. S.K. Das I.S.M.]
- Rock mechnics and Ground control, [D.Biswas]
- Practical coal mining [Grorgr L. Kerr]
- खान की गैसें व गैस टेस्टिंग
- माईनिंग डायजेस्ट
- सम आस्पेक्ट्स आफ माइन मैनेजमेण्ट लेजिस्लेशन एण्ड जनरल सेफ्टी भाग 13,14
- The use and misuse of Explosive in coal mining. [John Joseph]
- Coal mining methods in missouri [William wal bridge wegel]
- स्मारिका– अन्तर्क्षेत्रीय खान बचाव प्रतियोगिता 2009–10
- जमुना– कोतमा एरिया की भूमिगत खदानों एवं खुली खदानों की कार्य एवं प्रोडेकसन की टारगेट एवं टारगेट एचीवमेण्ट की मासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट।